श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो 40 रेलवे की लाइन हैं नान-वाइबिल निकली हैं, तो उनको बनाते समय क्या उनकी वाइबिलिटी को नहीं देखा गया था ? क्या रेल मंत्री बताएंगे कि इस प्रकार की नोन-वाइबल लाइनें दुबारा न बनें, इसके लिए क्या कोई सिस्टम इंटरोडयूस हो रहा है ?

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, ये लाइन्स कब की बनी हुई हैं, यह हिस्टोरिकल है। **(व्यवधान)** . . .हमारे पास जो रिपोर्ट हैं, ये दर्जनों कमेटी की रिपोर्ट हैं और यह सिलसिला आजादी के पहले से शुरू हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं।

श्री सभापति : नहीं, आप रहने दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें। यह इंडियन रेलवे इंक्वायरी कमेटी ने वर्ष 1936-37 में ही कहा था कि ये अनइकोनोमिक ब्रांच रेलवे लाइनें या अनवाइबल लाइनें हैं, उनको सरकार के खर्चे पर या रेलवे के खर्चे पर चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद वर्ष 1959 की कमेटी की रिपोर्ट है, पार्लियामेंटी कमेटी, रेलवे रिफोर्म्स कमेटी, पार्लियामेंट की डिफरेन्ट कमेटीज ने रिपोर्ट दी हैं कि इसको चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक इनका यह प्रश्न है कि बनाने के पहले क्यों नहीं देखते, तो बनाने के पहले तो देखा जाता है, लेकिन सिर्फ अगर लाभ को देखा जाए तो मेरे ख्याल से 90 प्रतिशत परियोजना, जो हाथ में ली हुई हैं, उनको ड्राप करना पड़ेगा।

* 583. [The qestioner (Shri Raju Parmar) was absant for answer vide Page 41-42 infra.]

Assistance to oilseeds producers

* 584. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 40 per cent of the domestic demand for edible oil is met through import;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps taken by Government to increase oilseeds production; and

(d) whether Government propose to provide financial assistance to producers of oilseeds?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) The details of production of oilseeds, edible oils and import of edible oils during last five years are given below :—

(Qty. in Lakh Metric Tonnes)

Sl. No.	Year	Production of oilseeds	Production of edible oils	Import of Edible oils
1.	1997-1998	213.20	60.32	12.66
2.	1998-1999	247.50	69.61	26.22
3.	1999-2000	207.10	60.14	41.96
4.	2000-2001	184.4	55.04	41.77
5.	2001-2002	204.6	61.22	42.14

The above table indicates that the import of edible oils as a percentage of total availability ranged from about 17 to 41.

(c) and (d) In order to increase the production of oilseeds in the country, a centrally sponsored Oilseeds Production Programme (OPP) is under implementation in 28 States covering 408 selected districts. Under the programme, financial assistance by way of subsidies on various inputs like production and distribution of seeds, distribution of seed minikits, distribution of improved farm implements, sprinkler sets, rhyzobium culture and frontline demonstrations etc. is provided to the farmers in order to induce them to take up the cultivation of oilseeds on a large scale. In addition Government also fixes the Minimum Support Prices for major oilseeds crops and market support is provided through National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED).

श्री सुरेश पचौरी : आदरणीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें स्वीकार किया है। जो एडीबल ऑयल का इम्पोर्ट है वह वर्ष 1997 से 2001-2002 के आंकड़े देखें तो उसके हिसाब से इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है और यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हिन्दुस्तान दुनिया का नंबर वन ऐसा देश है, जो एडीबल ऑइल को सबसे ज्यादा मात्रा में इम्पोर्ट कर रहा है। मैं आपके जरिए मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन ऑयल सीड की लगातार कम होती जा रही है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार यह प्लानिंग कर रही है कि वह कांट्रेक्ट फार्मिंग इन ऑयल सीड सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कोई लेजिस्लेशन लाएगी ? सरकारी सूत्रों से समाचार पत्रों में जो समाचार छपे हैं, उनसे यह जानकारी

मिलती है कि सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ स्पष्ट उत्तर दे सकेंगे।

श्री अजित सिंह : सभापति जी, कांट्रेक्ट फार्मिंग के स्टेट के अंदर जो लाज हैं, एपीएमसी लाज, एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्केटिंग के लाज उसके अंदर यह हो सकता है। हमारी जो कई मीटिंग हुई थीं इनकी एसोसिएशन के साथ, एडीबल ऑयल प्रोड्यूसर्स के साथ, जिसमें राजस्थान सरकार के लोग भी शामिल थे, उसमें यह एक सजेशन आया था कि इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसमें कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन जहां तक कांट्रेक्ट फार्मिंग का सवाल है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट उनके जो एपीएमसी के लाज हैं, उनको चेंज करके ही एलाऊ कर सकते हैं।

श्री सुरेश पचौरी : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो टेक्नालोजी मिशन है ऑयल सीडॅस के मामले में, उसकी परफोरमेन्स के बारे में, जो टीएमओ की परफोरमेन्स है, उस परफोरमेन्स से क्या माननीय मंत्री जी संतुष्ट हैं ? यदि उसमें वे कुछ विसंगतियां या खामियां पाते हैं तो क्या उसको रीवेम्प करने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री अजित सिंह : सभापति महोदय, टीएमओ 1985-86 में बना था। 80 के दशक में ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में 5.2 प्रतिशत की इन्क्रीज़ हुई थी, 90 के दशक में 2.13 प्रतिशत की इन्क्रीज़ हुई है और 10वीं योजना में हमारा प्लान 6 प्रतिशत इन्क्रीज़ करने का है। टीएमओ काम कर रहा है, इसको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है। ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत हम समझ रहे हैं और इसको किस तरह से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उसकी तरफ हम प्रयासरत् हैं।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA : Sir, it is mentioned in the Annual Report of Agriculture, 2002-2003, page 21, column 2, that productivity increase of about 60 per cent in oilseeds is possible with the existing technology. I would like to know from the hon. Minister what is the hindrance in going for increased acreage under oilseed cultivation. The Government is providing one-tonne-per-day capacity oil Expellor, one for one village. I would like to know whether local consumption of the edible oil for rural poor can be met out of local production.

SHRI AJIT SINGH : Sir, the first thing is that productivity constraints are there in oilseeds because, mostly, they are grown in the rainfed areas where the vagaries of nature decide how much production would be there. If there is drought, the area goes down, if there is good rain, the area goes up. Also, there is lack of good seeds in oilseeds. The farmer also does not want to spend too much time because he does not know how the crop would be. But our research system is working, and they have come up with some new hybrid seeds.

Now, I come to the second part of the question. Obviously, the need is not met locally. It might be met in some local areas where the production is there like,

in Rajasthan, in Uttar Pradesh, and in some other States. But, we import about 40 per cent of our requirement; so, obviously, the needs are not met locally.

Metal Contents in vegetables

* 585. SHRI NANA DESHMUKH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether high level of lead, copper, zinc and cadmium have been noticed in okra (bhindi), cauliflower and spinach vegetables grown and sold in Delhi and Varanasi;

(b) if so, what are Government's findings; and

(c) the steps being taken by Government to check the growth of metals and making the vegetables safe for human consumption?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Some samples of Okra (Bhindi), Palak and Cauliflower vegetables collected from field and market outlets of Delhi and Varanasi are reported to have shown high level of zinc, lead and cadmium.

(b) A study was carried out by the Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi and Banaras Hindu University (BHU), Varanasi in collaboration with the Imperial College of London, UK on heavy metel contamination of vegetables in peri-urban agriculture.

At IARI, New Delhi, vegetable samples of palak, okra and cauliflower were collected from the peri-urban areas of Delhi (Yamunapusta, Okhla, Ballabhagarh, Najafgarh and Alipur) and their nearby markets during 2001 and 2002. The study showed that some of the samples collected from Yamunapusta, Najafgarh and Okhla had higher level of contamination with zinc, lead and cadmium. However, none of the samples showed higher level of copper.

At BHU, Varanasi, the study was undertaken on limited number of samples collected from vegetable market. Most of the samples had the level of cadmium above the permissible limits. Some samples also had higher level of lead and copper. However, most of the samples showed lower level of zinc. This